RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 349
दि. 22.04.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

त्रिशूर में भीषण विस्फोट: पटाखा यूनिट हादसे ने ली 12 जिंदगियां, उत्सव की तैयारियों के बीच मची अफरा-तफरी

(जीएनएस)। त्रिशूर। केरल के त्रिशूर जिले के मुंडथिक्कोडु इलाके में मंगलवार को हुए भीषण विस्फोट ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। एक पटाखा निर्माण यूनिट में हुए इस धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। यह हादसा उस समय हुआ, जब प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं और आतिशबाजी के सैंपल तैयार किए जा रहे थे।

बताया जा रहा है कि विस्फोट के समय यूनिट में करीब 40 लोग काम कर रहे थे। दोपहर का समय होने के कारण कर्मचारियों के लिए भोजन भी वहीं लाया गया था, जिससे एक साथ अधिक संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक हुए धमाके ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सात लोग किसी तरह मौके से भागने में सफल रहे, जबकि बाकी लोग धमाके और आग की चपेट में आ गए।

सूत्रों के मुताबिक, जिस यूनिट में यह हादसा हुआ, वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। माना जा रहा है कि किसी कारणवश आग लगने के बाद यह सामग्री एक साथ फट गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो।

विस्फोट के तुरंत बाद इलाके में घना धुआं और आग फैल गई, जिससे बचाव कार्यों में भारी कठिनाई आई। घटनास्थल पर अधजले और बिना फटे विस्फोटकों की मौजूदगी के कारण राहत और बचाव टीमों को बेहद सतर्कता के साथ काम करना पड़ा। पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की।

घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जिनमें त्रिशूर मेडिकल कॉलेज प्रमुख है। अस्पताल प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, जिससे बड़ी संख्या में घायलों का इलाज तुरंत शुरू किया जा सके। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें विशेष चिकित्सा निगरानी में रखा गया है।

इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आसपास के गांवों और कस्बों में रहने वाले लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ समय के लिए जनजीवन पूरी तरह ठहर सा गया और हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

इस हादसे पर नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है।

प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री वहां कैसे रखी गई और सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं हुआ। प्रारंभिक तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि सुरक्षा नियमों में लापरवाही या मानकों की अनदेखी इस हादसे का कारण हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखा निर्माण और भंडारण से जुड़े कार्य बेहद संवेदनशील होते हैं और इनमें जरा सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। खासकर त्रिशूर पूरम जैसे बड़े उत्सव के दौरान, जब भारी मात्रा में आतिशबाजी तैयार की जाती है, तब सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना और भी जरूरी हो जाता है।

राज्य सरकार अब इस घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की तैयारी में है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और पटाखा उद्योग से जुड़े सभी इकाइयों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो।

यह हादसा न केवल उन परिवारों के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि यह एक बड़ी चेतावनी भी है कि विकास और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। त्रिशूर की इस त्रासदी ने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी हो सकती है।

बंधुआ मजदूरी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी रेस्क्यू के बाद भी हजारों बच्चे इंतजार में

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर न्यायपालिका ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को तीखी टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अब केवल कागजी दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब तक इस समस्या के समाधान के लिए वास्तविक रूप से क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत की सख्ती का मुख्य कारण वे आंकड़े हैं, जो सुनवाई के दौरान सामने आए। वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न अभियानों के तहत लगभग 11 हजार बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 971 बच्चों को ही अब तक सरकारी आर्थिक सहायता मिल पाई है। यह आंकड़ा न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रेस्क्यू के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया कितनी कमजोर है। हजारों बच्चे आज भी सरकारी मदद और पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं, जो इस पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि उन्हें सिर्फ यह नहीं जानना है कि कितने बच्चों को बचाया गया, बल्कि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि बचाए जाने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया। अदालत ने सरकार से सीधे तौर पर पूछा कि इस "अभिशाप" को जड़ से खत्म करने के लिए क्या ठोस रणनीति बनाई गई है और क्या न्यायपालिका से किसी अतिरिक्त दिशा-निर्देश की आवश्यकता है। यह सवाल अपने आप में इस बात का संकेत है कि कोर्ट अब इस मुद्दे को केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी देख रहा है।

मामले में एक और गंभीर पहलू अंतरराज्यीय समन्वय की कमी को लेकर सामने आया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब एक राज्य के बच्चों को दूसरे राज्य में ले जाकर बंधुआ बनाया जाता है, तो राज्यों के बीच तालमेल की कमी के कारण रेस्क्यू और राहत कार्य प्रभावित होते हैं। कई मामलों में बच्चे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए जाते हैं, लेकिन उनके बचाव और पुनर्वास की प्रक्रिया में प्रशासनिक बाधाएं आ जाती हैं। इस पर पीठ ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक सरल और प्रभावी प्रणाली विकसित करे, जिससे पीड़ितों को तुरंत सहायता मिल सके।

इस पूरे मामले की जड़ 2022 की एक याचिका से जुड़ी है, जब बिहार के गया जिले के कुछ मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई थी। इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ईंट भट्ठों पर बंधुआ बनाकर रखा गया था। उन्हें बिना पंजीकरण वाले ठेकेदारों के जरिए काम पर लगाया गया, जहां न तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी और न ही आने-जाने की स्वतंत्रता थी। यह स्थिति आधुनिक समय में भी गुलामी जैसे हालात को दर्शाती है। हालांकि 2019 में उन्हें मुक्त करा लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न्याय और पुनर्वास के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, जो सिस्टम की धीमी कार्यप्रणाली को उजागर करता है। अदालत की टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि अब केवल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती उन बच्चों और मजदूरों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है, जिन्हें वर्षों तक शोषण का सामना करना पड़ा है। यदि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, तो उनके दोबारा शोषण का शिकार बनने का खतरा बना रहता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई केवल कानून के जरिए नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। जागरूकता, सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 मई 2026 की तारीख तय की है। तब तक केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर एक विस्तृत कार्ययोजना पेश करनी होगी। अदालत की यह सख्ती इस बात का संकेत है कि अब इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह मामला न केवल प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न है, बल्कि यह उन हजारों बच्चों और मजदूरों के भविष्य से भी जुड़ा है, जो आज भी शोषण और असुरक्षा के साये में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल उम्मीद जगाती है कि आने वाले समय में इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिससे बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सके।

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता पर संशय, बयानबाजी से बढ़ा तनाव; ट्रंप बोले—मजबूत स्थिति में है अमेरिका

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पश्चिम एशिया की संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थिति एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की शांति वार्ता पर संशय के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। दो सप्ताह के युद्धविराम की समयसीमा समाप्ति के करीब है, लेकिन दोनों देश अब भी अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे संवाद की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं। 11 और 12 अप्रैल को हुई पहले दौर की वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। इसके बाद क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की और दूसरे दौर की बातचीत के लिए इस्लामाबाद को मंच के रूप में तैयार किया। पाकिस्तान प्रशासन ने संभावित वार्ता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, जिनमें हजारों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती शामिल थी। हालांकि, तमाम तैयारियों के बावजूद स्थिति उस समय और उलझ गई जब तय समय तक न तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा और न ही ईरान का कोई आधिकारिक दल वहां दिखाई दिया। इससे वार्ता के भविष्य को लेकर असमंजस और गहरा गया। कुछ रिपोर्टों में यह संकेत जरूर मिले कि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि पहले से पाकिस्तान में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर किसी ठोस प्रगति की पुष्टि नहीं हुई।

इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका "बहुत मजबूत स्थिति" में है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका किसी भी समझौते के लिए तैयार है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार और शेयर बाजार पर पड़ सकता है, जो पहले से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं।

दूसरी ओर, तेहरान की रणनीति भी कम आक्रामक नहीं दिख रही। ईरान इस वार्ता में अपने सामरिक प्रभाव का उपयोग करना चाहता है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण को एक दबाव के साधन के रूप में देख रहा है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, और यहां किसी भी प्रकार का तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों को सीधे प्रभावित कर सकता है। ईरान की कोशिश है कि वह किसी ऐसे समझौते पर पहुंचे, जिससे उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिले, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई कठोर अंकुश न लगे।

मंगलवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दोनों देशों के राजदूतों से मुलाकात कर वार्ता की संभावनाओं को जीवित रखने का प्रयास किया। यह बैठक इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब भी इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच जारी तीखी बयानबाजी ने माहौल को और जटिल बना दिया है, जिससे किसी भी समझौते तक पहुंचना फिलहाल आसान नहीं दिख रहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह गतिरोध केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति जैसे कई बड़े कारक जुड़े हुए हैं। अमेरिका जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना चाहता है, वहीं ईरान अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दबाव में आने को तैयार नहीं है।

फिलहाल, पूरी दुनिया की नजर इस संभावित वार्ता पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि या तो दोनों देश बातचीत के दूसरे दौर के लिए सहमत होंगे या फिर कम से कम युद्धविराम की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी और अनिश्चितता इस समय देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि शांति की राह अभी भी कठिन और जटिल बनी हुई है।

2500 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा: बैंकिंग सिस्टम में सेंध, अंदरूनी मिलीभगत से खड़ा हुआ विशाल घोटाला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। डिजिटल लेन-देन के तेजी से बढ़ते दौर में साइबर अपराधों का खतरा भी उतनी ही तेजी से गहराता जा रहा है, और गुजरात के राजकोट से सामने आया 2500 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड इस खतरे की गंभीरता को साफ तौर पर उजागर करता है। इस मामले में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनमें अब निजी बैंकों के अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। यह मामला सिर्फ एक साइबर ठगी नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम के भीतर तक पैठ बना चुके एक संगठित नेटवर्क की कहानी बनता जा रहा है।

राजकोट ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय गुर्जर के नेतृत्व में चल रही जांच में अब तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में इस मामले में तीन और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें विभिन्न निजी बैंकों के अधिकारी शामिल हैं। इनमें Yes Bank के पर्सनल मैनेजर मौलिक कामानी, Axis Bank के जामनगर स्थित मैनेजर कल्पेश डांगरिया और HDFC Bank के पर्सनल बैंकर अनुराग बाल्धा शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी ने इस पूरे नेटवर्क के काम करने के तरीके को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस जांच के अनुसार, इस साइबर फ्रॉड का पूरा ढांचा बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया था। इसमें फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये का लेन-देन किया जाता था और फिर उस रकम को हवाला चैनलों के जरिए आगे भेज दिया जाता

था। अब तक इस रैकेट से जुड़े 85 फर्जी बैंक खातों की पहचान की जा चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि यह नेटवर्क कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा था।

गिरफ्तार किए गए बैंक अधिकारियों की भूमिका इस मामले में बेहद अहम मानी जा रही है। आरोप है कि मौलिक कामानी ने पहले से गिरफ्तार आरोपियों की मदद करते हुए संदिग्ध खातों को खोलने और उन्हें सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कई तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इन खातों को इस तरह संचालित किया कि बड़े पैमाने पर होने वाले लेन-देन के बावजूद बैंक की ओर से जारी होने वाले अलर्ट सिस्टम को चकमा दिया जा सके। यह दर्शाता है कि सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने के साथ-साथ अंदरूनी जानकारी का भी दुरुपयोग किया गया।

वहीं कल्पेश डांगरिया पर आरोप है कि उसने नकली पहचान के आधार पर खाते खुलवाने में मदद की। यह प्रक्रिया आमतौर पर बैंकिंग नियमों के तहत बेहद सख्त होती है, लेकिन इस मामले में नियमों की अनदेखी करते हुए ऐसे खाते खोले गए, जिनका इस्तेमाल बाद में अवैध लेन-देन के लिए किया गया।

दूसरी ओर अनुराग बाल्धा ने वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर इन खातों को वैधता प्रदान की, जिससे यह पूरा नेटवर्क बिना किसी संदेह के लंबे समय तक सक्रिय रह सका।

जांच एजेंसियों का कहना है कि इन खातों से नकदी निकालने में भी इन अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। नकदी को बाद में हवाला के जरिए अन्य स्थानों पर भेजा जाता था, जिससे पैसे के स्रोत और गंतव्य का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता था। यह पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि यह केवल ऑनलाइन फ्रॉड तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें ऑफलाइन नेटवर्क और वित्तीय चैनलों का भी पूरा इस्तेमाल किया गया।

इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साइबर क्राइम पोर्टल पर इस रैकेट से जुड़ी अब तक 535 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। यह संख्या लगातार बढ़ भी सकती है, क्योंकि जांच के दौरान और भी पीड़ितों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर हुई ठगी ने न केवल आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता को भी चुनौती दी है।

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों बैंक अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पहले से गिरफ्तार अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घोटाले के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं और क्या इसके तार देश के बाहर तक भी जुड़े हुए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि अपराधी तकनीक और सिस्टम की खामियों का बेहद चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। जब इसमें अंदरूनी लोगों की मिलीभगत भी जुड़ जाती है, तो ऐसे नेटवर्क को पकड़ना और भी कठिन हो जाता है। यही वजह है कि इस मामले को एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जहां बैंकिंग संस्थानों को अपने सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

यह मामला आम नागरिकों के लिए भी एक बड़ा सबक है कि वे अपने बैंकिंग लेन-देन को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। डिजिटल युग में जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं जोखिम भी उतने ही बढ़ गए हैं, और ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव बन सकती है।

गुजरात के इस 2500 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर तकनीक और संस्थागत कमजोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकिंग संस्थानों और आम जनता को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह के बड़े घोटालों को रोका जा सके और वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखा जा सके।

संपादकीय

छात्रों का आत्मघात

कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दो महीनों के दौरान चार छात्रों द्वारा आत्महत्या करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह संस्थान ही नहीं, शैक्षिक जगत और उनके परिवारों की भी अपूरणीय क्षति है। घटनाएं तकनीकी संस्थानों में तनाव प्रबंधन और मानसिक उपचार की खामियों को भी उजागर करती हैं। कोई व्यक्ति आत्मघाती कदम तब ही उठाता है जब उसे उम्मीद के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। इस घातक कदम को उठाने से पहले वो तनाव के चरम से जूझते हुए किस मानसिक कष्ट से गुजरता होगा, अंदाज लगाना कठिन नहीं है। उसकी मनःस्थिति इतनी हताशा से भरी होती है कि आत्महत्या जैसा पीड़ादायक-घातक रास्ता उसे समाधान नजर आता है। विडंबना है कि हम संभावनाओं के इस दुखद अंत को मूकदर्शक बने देखते हैं। हम आत्महत्या के आंकड़ों व संख्या का जिक्र ही करते हैं, लेकिन उसे पाल-पोसकर बड़ा करने वाले मां-बाप पर हुए वज्रपात का अहसास नहीं करते। उच्च तकनीकी संस्थान की दहलीज तक पहुंचने में बच्चे कितना शरीर को गलाते हैं। उन्हें पालने-पोसने व बड़ा करने में मां-बाप अपना खून पसीना एक कर देते हैं। हर बच्चा चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। उसके इस मुकाम तक पहुंचने में माता-पिता का त्याग शामिल होता है। कई अभिभावक बैंकों से कर्ज लेकर इन तकनीकी संस्थानों में बच्चों का एडमिशन कराते हैं। कई पैरेंट्स इस लायक बनाने के लिये पैसा कोचिंग संस्थानों में बहाते हैं। फिर एक दिन खबर आती है कि उनकी उम्मीदों ने आत्मघात कर लिया। हमें उनके दर्द को अपने दर्द की तरह महसूस करना चाहिए। इन घटनाओं के बाद एनआईटी ने एक पांच सदस्यीय जांच समिति बनायी है। लेकिन क्या समिति उन बच्चों का जीवन लौटा पाएगी? दूसरी ओर राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से प्रकरण में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं एनआईटी ने छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिये कुछ अलग समितियां भी बनायी हैं। देश के विभिन्न उच्च तकनीकी संस्थानों में छात्रों के आत्मघात की खबरें अकसर आती हैं। कुछ साल पहले शिक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया था कि साल 2018-2023 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों के 98 छात्रों ने आत्महत्या की थी। इनमें सबसे ज्यादा सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी में हुई थी। उसके बाद आत्मघात करने वाले छात्र एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के थे। जाहिर है इन संस्थानों में कुछ तो ऐसा घट रहा है, जिससे हमारी संवेदनशील प्रतिभाएं साम्य नहीं बैठा पा रही हैं। विडंबना यह है कि देश के हर संस्थान व शासन-प्रशासन के स्तर पर आग लगने पर कुआं खोदने की मनोवृत्ति बनी हुई है। इन संस्थानों में पूरे देश की चुनिंदा प्रतिभाएं ही पहुंचती हैं। जो एक गलाकाट स्पर्धा के दौर से गुजरकर यहां तक आती हैं। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा ऐसा है जो बच्चों को किताबी कीड़ा तो बनाता है, लेकिन चुनौतियों से जूझने लायक नहीं बनाता। अब वे शिक्षक भी नहीं रहे जो छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर पढ़ाएं। बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जिनकी प्राथमिकता अपने विषय और वेतन-भत्तों व सुविधाओं तक ही सीमित रह गई है। परवरिश के स्तर पर भी नहीं सिखाया जाता कि जीवन में बुरे से बुरा घटने पर बिना विचलित हुए कैसे उस चुनौती का सामना किया जाए। परिवार की उम्मीदों का बोझ ढोते, ये प्रतिभावान बच्चे जब असफलता के भय से ग्रस्त होते हैं तो आत्महत्या को अंतिम विकल्प के रूप में सोचने लगते हैं। ऐसी घटनाएं होने पर शिक्षण संस्थानों द्वारा फौरी तौर पर जो कदम उठाये जाते हैं, वे कारगर साबित नहीं होते। किसी आत्महत्या का मामला प्रकाश में आने के बाद हाय-तौबा होती है, तब घोषणाएं होती हैं। फिर वही ढाक के तीन पात। तनाव से गुजरते छात्रों पर पैनी नजर रखने की जरूरत होती है। ये बच्चे बेहद संवेदनशील व ईमानदार होते हैं, जो अपने को साबित न कर पाने पर आत्मघात की राह चुन लेते हैं। समय रहते उनकी पहचान करके संस्थान प्रबंधन व अभिभावकों को उनकी मनोवैज्ञानिक सहायता करनी चाहिए। इन प्रतिभाओं को तनाव के दानव का ग्रास बनने से रोके जाने की जरूरत है।

हिमालयी पर्यावरण को तीर्थयात्रियों के दबाव से बचाएं

> हिमालय की अति संवेदनशील पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा के लिए प्रतिदिन तीर्थयात्रियों की संख्या तय होनी जरूरी है। लेकिन स्थानीय हितधारकों के दबाव के चलते राज्य में यह सीमा एक बार लागू करके वापस ले ली गयी। बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।

अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ग्रीष्मकाल के लिए शुरू हो चुकी है। देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु ऑनलाइन यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि हिमालय की अति संवेदनशील पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए आखिर कितने तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा एक ही दिन में एक साथ कर सकते हैं।

हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी भी बार-बार उत्तराखंड सरकार पर जोर डाल रहा है कि वह चारों धामों की कैरीइंग कैपेसिटी (धारण क्षमता) का वैज्ञानिक अध्ययन करवाकर रिपोर्ट पेश करे ताकि कानूनन आगंतुकों की संख्या तय की जा सके। लेकिन होटल, ढाबा, पुजारियों और अन्य हितधारकों का इतना दबाव है कि उनकी नाराजगी से सीधे राजनीतिक संभावनाओं पर असर का जोखिम है। इसी दबाव के चलते 2022 में यात्रियों की तय सीमा को 2023 में स्वयं ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब एनजीटी व पर्यावरणवादी इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार, पहले से ही बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के संकट से घिरे इस क्षेत्र पर त्रासदियों की संख्या और आवृत्तियों में वृद्धि होती जा रही है। हिमालय एशिया का जलस्तंभ होने के साथ ही उपमहाद्वीप का मौसम नियंत्रक भी है, इसलिये हिमालय के संकट को मात्र स्थानिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।

पिछले 25 साल में उत्तराखंड स्थित चारों हिमालयी धामों में यात्रियों के साथ ही वाहनों की संख्या भी कई गुना बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल यात्रियों की संख्या वर्ष 2025 में

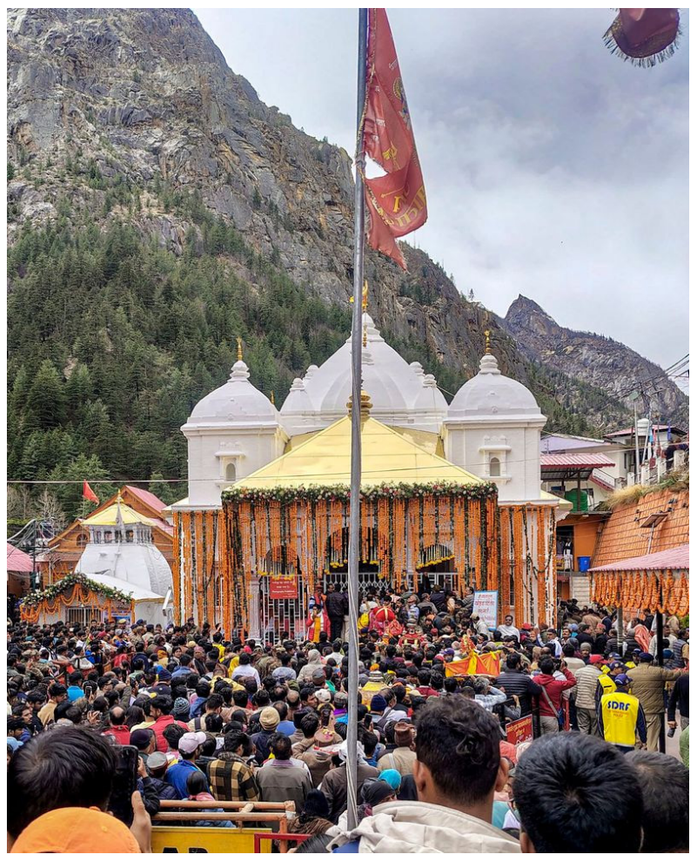

51,09,848 तक पहुंच गई है। वहीं वाहनों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। वाहनों से जो प्रदूषणकारी उत्सर्जन होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फोटोकैमिकल ऑक्सीडेंट, वायु विष यानी बेंजीन, एल्डिहाइड, ब्यूटाडीन, सीसा, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन व सल्फर के ऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। पर्यावरणविदों के लिए एक और चिंता का विषय ब्लैक कार्बन है, जो कि जलवायु परिवर्तन करने के साथ ही ग्लेशियरों को भी पिघला रहा है।

एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को आगामी 21 जुलाई से पहले चारों धामों में भीड़ की दृष्टि से वहन क्षमता को लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है। वास्तव में हिमालयी क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण की कवायद सदा से विवादों और दबावों के घेरे में रही है। राज्य सरकार ने 2022 में साहसिक निर्णय लेते हुए प्रतिदिन यात्रियों की संख्या निर्धारित की थी, जिसमें बद्रीनाथ के लिए 15 हजार और केदारनाथ के लिए 12 हजार जैसी सीमाएं तय थीं। इसे सुरक्षा की दिशा में मानक कदम माना गया था। लेकिन वर्ष 2023 आते-आते स्थानीय व्यावसायिक हितों और हितधारकों के आर्थिक दबाव के चलते यह सीमा हटा ली गई। होटल व्यवसायियों व परिवहन संचालकों की अल्पकालिक आर्थिक चिंताओं ने दीर्घकालिक सुरक्षा जोखिमों को पीछे धकेल दिया।

वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और आईआईटी रुड़की के शोध इशारा करते हैं कि हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों की अपनी एक भौतिक सीमा है। वैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक धाम की भौगोलिक बनावट, ढलानों की स्थिरता और वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन भिन्न हैं। आईआईटी रुड़की के आपदा विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक मानवीय गतिविधियों और भारी निर्माण कार्य से ढलानों की 'इंटरनल बाइंडिंग' कमजोर होती है, जिससे भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब इन अस्थिर ढलानों पर वाहनों और लोगों का अतिरिक्त भार पड़ता है, तो यह किसी बड़े भूगर्भीय असंतुलन का ट्रिगर बन सकता है।

भीड़ का प्रभाव केवल सड़कों पर जाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वैज्ञानिक दुष्परिणाम कहीं अधिक गहरे हैं। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के शोध बताते हैं कि अचानक बढ़ने वाली जनसंख्या से हिमालयी जल स्रोतों और स्प्रिंग्स (नौलेधारों) पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे स्थानीय जल चक्र प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त, कचरा प्रबंधन चुनौती बनकर उभरा है। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक यात्री द्वारा छोड़ा गया प्लास्टिक और जैविक कचरा संवेदनशील ग्लेशियरों के समीप एकत्र होकर वहां के तापमान और पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रहा है। कचरे का यह ढेर अंततः अलकनंदा और भागीरथी जैसी पवित्र नदियों की जल गुणवत्ता को प्रदूषित कर रहा है, जिसका प्रभाव पहाड़ों से लेकर गंगा के मैदानी इलाकों तक देखा जा सकता है।

विश्व प्रसिद्ध भीड़ वैज्ञानिक डिर्क हेल्बिंग के अनुसार, जब किसी सीमित स्थान पर घनत्व चार व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो जाता है, तो वहां 'क्राउड टर्बुलेंस' की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में व्यक्ति की अपनी गति समाप्त हो जाती है और वह भीड़ के दबाव में एक तरल पदार्थ की तरह बहने लगता है। चारधाम के संकरे मंदिर परिसरों और खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों पर ऐसी स्थिति किसी भी क्षण भगदड़ या जनहानि का कारण बन सकती है।

शासन और समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस धारणा को बदलने की है कि यात्रियों की संख्या सीमित करना आस्था पर प्रहार है। वास्तव में, यह आस्था को सुरक्षित करने का ही एक उपक्रम है। हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए अब डिजिटल पंजीकरण, स्लॉट आधारित दर्शन और 'एंट्री-एग्जिट' नियंत्रण जैसे आधुनिक प्रबंधनों को बिना किसी राजनीतिक या व्यावसायिक दबाव के लागू करना होगा। स्थानीय समुदायों को भी यह समझना होगा कि यदि हिमालय सुरक्षित नहीं रहा, तो उनकी आजीविका का यह आधार ही सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।

प्रेरणा

पपीहे की अटूट निष्ठा और सच्ची भक्ति का गूढ़ रहस्य

भक्ति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो मनुष्य के अंतर्मन को झकझोर देती है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। यह कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर की वह अग्नि है जो साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निरंतर जलती रहती है। इसी भक्ति की गहराई को समझाने के लिए संत कबीर ने एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग प्रस्तुत किया, जो आज भी हर साधक के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।

एक दिन कबीर अपने शिष्यों के साथ गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे। वातावरण में एक दिव्य शांति थी, गंगा की लहरें मधुर ध्वनि कर रही थीं और प्रकृति मानो अपने आप में लीन थी। उसी समय उनकी दृष्टि एक छोटे से पक्षी पर पड़ी, जो अत्यंत व्याकुल अवस्था में था। वह पपीहा था, जिसे भारतीय परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वर्षा की बूंद ही पीता है और किसी अन्य जल को ग्रहण नहीं करता, चाहे उसकी प्यास कितनी भी प्रबल क्यों न हो।

वह पपीहा अत्यधिक प्यास से तड़प रहा था और असंतुलित होकर गंगा के जल में गिर पड़ा था। उसके चारों ओर जल ही जल था, उसकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद था, लेकिन फिर भी उसने अपनी चोंच नहीं खोली। वह संघर्ष कर रहा था, तड़प रहा था, लेकिन अपनी निष्ठा से विचलित नहीं हो रहा था। यह दृश्य देखकर कबीर और उनके शिष्य आश्चर्यचकित रह गए।

कबीर ने अपने शिष्यों से कहा कि इस छोटे से पक्षी की निष्ठा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। उन्होंने कहा कि जब वे इस पपीहे की अटूट भक्ति को देखते हैं, तो उन्हें अपनी भक्ति भी बहुत छोटी लगने लगती है। यह पक्षी हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है—ऐसी भक्ति जिसमें कोई समझौता नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, केवल एक लक्ष्य होता है और उसी के लिए पूरा जीवन समर्पित होता है।

पपीहे की यह विशेषता केवल एक प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। यह हमें यह समझाता है कि जब तक हमारे भीतर अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। आज के समय में मनुष्य हर चीज को आसान और त्वरित तरीके से पाना चाहता है। वह थोड़ी सी कठिनाई आने पर ही अपने मार्ग से भटक जाता है और दूसरे विकल्पों की तलाश करने लगता है। लेकिन पपीहा हमें यह सिखाता है कि यदि लक्ष्य सच्चा और उच्च है, तो उसके लिए धैर्य और दृढ़ता भी उतनी ही आवश्यक है।

भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, जिसमें व्यक्ति को अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह-माया से ऊपर उठना पड़ता है। यह यात्रा तभी संभव है जब साधक के भीतर अपने ईश्वर या अपने गुरु के प्रति वही तड़प हो, जो पपीहे के भीतर स्वाति की बूंद के लिए होती है। जब यह तड़प जागृत होती है, तब व्यक्ति के लिए संसार के अन्य सभी आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

कबीर ने यह भी बताया कि सच्ची भक्ति में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। पपीहा महीनों तक स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा करता है, वह अपनी प्यास को सहन करता है, लेकिन अपनी निष्ठा से समझौता नहीं करता। इसी प्रकार, एक सच्चा साधक भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि सही समय आने पर उसे उसका फल अवश्य मिलेगा।

इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी भक्ति भी इतनी ही शुद्ध और अटूट है, या फिर हम केवल परिस्थितियों के अनुसार अपनी आस्था बदलते रहते हैं। यदि हमारी भक्ति में स्थिरता नहीं है, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है और यह समझने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं।

पपीहा हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई द्वंद्व नहीं होता। जब तक हमारे मन में यह विचार रहता है कि यदि यह मार्ग कठिन हो जाए तो हम कोई दूसरा मार्ग चुन लेंगे, तब तक हमारी भक्ति अधूरी रहती है। सच्चा साधक वही होता है, जो हर परिस्थिति में अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगता।

आज के आधुनिक युग में, जहाँ मनुष्य भौतिक सुखों और तात्कालिक लाभों में उलझा हुआ है, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। यह हमें यह समझाती है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की उस भावना में है, जो हमें हमारे ईश्वर से जोड़ती है। जब यह भावना प्रबल होती है, तब व्यक्ति के लिए जीवन के सभी कष्ट और कठिनाइयाँ भी अर्थहीन हो जाती हैं।

कबीर का यह संदेश केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति पपीहे जैसी निष्ठा और समर्पण रखें, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या कोई अन्य कार्य, यदि हमारे भीतर दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अंततः, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। यह केवल पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं और अपने भीतर सच्ची निष्ठा को बनाए रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में भक्त कहलाने के योग्य बनते हैं।

दो भाई, दोनों तबाही...क्या है भारत-रूस का RELOS समझौता? चीन पाक और US की हेकड़ी निकली

दो भाई और दोनों तबाही। चीन, पाकिस्तान और यूएस की हेकड़ी निकाल दी। एक पैक्ट, एक समझौता जो हुआ है भारत और रूस के बीच। भारत और रूस के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और गहराते डिफेंस कोऑपरेशन को दर्शाते हुए एक अहम समझौता औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। भारत और रशिया के बीच द रेलॉस एग्रीमेंट हुआ है। इस फैक्ट के तहत दोनों देश एक दूसरे की टेरिटरी में अधिकतम 3000 मिलिट्री पर्सनल तैनात कर सकेंगे। सिर्फ सैनिक ही नहीं इस एग्रीमेंट के तहत शिप्स और एयरक्राफ्ट को भी एक दूसरे के क्षेत्र में तैनात करने की अनुमति दे दी गई है। यह समझौता रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी रेलोस से जुड़ा हुआ है। जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ज़, ट्रेनिंग और ह्यूमैनिटेरियन मिशनस जैसे पहलू भी शामिल हैं। हाल ही में भारत दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन ने इस इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को रटिफाई करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस एग्रीमेंट का मकसद भारत और रूस के बीच मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, पोर्ट्स पर वॉरशिप्स की डॉकिंग और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस और एयर फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क तैयार करना है। द इंडियन रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना रशिया के कुछ चुनिंदा सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएगी। ठीक वैसे ही रशिया भी जरूरत पड़ी तो भारत के कुछ सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेगा। यह समझौता कुछ कुछ-कुछ वैसा ही है जैसे अमेरिका मित्र देशों के सैन्य ठिकानों को अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही भारत और रशिया समय आने पर इसी तरह से एक दूसरे की जमीन का इस्तेमाल करेंगे अगर युद्ध में जरूरत पड़ती। जब दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे ताकतवर सेनाएं एक साथ मिलकर खड़ी होंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। रूस और भारत ने अपनी दोस्ती को एक कदम आगे ले जाते हुए एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी की है जिसे देखकर दुनिया की कई महाशक्तियों के माथे पर सिकन नजर आने लगी है। भारत और रूस ने एक ऐसा समझौता किया जिससे दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे भारतीय सेना की पहुंच आर्कटिक क्षेत्र तक और रूस की पहुंच हिंद महासागर तक हो जाएगी। इन दोनों ताकतवर देशों ने पल-पल बदल रही वैश्विक परिस्थितियों और जंग के माहौल के बीच यह समझौता अमल में लाकर दुश्मनों को परेशान कर दिया है। भारत और रूस के बीच द रेलॉस एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर अस्थाई बेस बना सकेंगे।

ईरान युद्ध में हमने देखा कि हवाई हमलों के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों में बने अपने सैन्य ठिकानों की मदद ली। अमेरिका से सीधे ईरान पर हमले करना खर्चीला है और समय भी काफी लगता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने ऑपरेशंस के लिए यूरोपीय देशों और मिडिल ईस्ट के भी कई देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इनमें कुछ स्थाई है और कुछ अस्थाई। ठीक वैसे ही अब से भारत और रूस एक दूसरे के सैनिक ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत के लिए रिलोस एग्रीमेंट रणनीतिक रूप से काफी फायदेमंद है। इससे भारतीय सेना की पहुंच आर्थिक क्षेत्र तक हो जाएगी। दुनिया की लगभग सभी महाशक्तियां जैसे अमेरिका, रूस और चाइना इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अभी तक भारत और रूस एक दूसरे के किन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के बाद भारतीय सेना रूस के एक बड़े पोर्ट मुरबंस और नॉर्दन प्लीट के मुख्यालय सिविरो म्स पर अपनी तैनाती कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो इससे भारतीय नौसेना की वैश्विक मौजूदगी बढ़ेगी और दूरदराज के सैन्य ऑपरेशन आसान हो जाएंगे। युद्ध की स्थिति में युद्धपोतों को बार-बार भारत वापस नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा चाइना के पास ब्लादी बोस्टोक पर भी भारतीय सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा कामचटका पर भी भारतीय सेना की रणनीतिक मौजूदगी हो सकती है। यह भी महत्वपूर्ण ठिकाना होगा। इसके अलावा रूस भी भारतीय सैन्य ठिकानों पर अपनी मौजूदगी से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर दबदबा बढ़ा सकता है। इस पूरे क्षेत्र पर दोनों देशों की मौजूदगी से अमेरिका और चाइना जैसे देशों को काउंटर करने में मदद मिलेगी। यह समझौता एक बार में 5 वर्षों तक के लिए किया गया है और इसके बाद दोनों देश इसे अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा सकते हैं। हालांकि भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया से भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट से जुड़े समझौते किए हैं। लेकिन इन सभी देशों के साथ रूस जैसा समझौता नहीं है। इन समझौतों के तहत भारतीय सेना को इन देशों की तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन इसमें सैनिकों की तैनाती की बात नहीं है। जबकि रेलॉस एग्रीमेंट के तहत भारतीय सेना रूस में भी सैनिक रख सकती है। पिछले साल आई सिपली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और रूस भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है।

अभियान

श्रीकृष्ण की लीला-यात्रा और भक्ति में डूबा आत्मा का मार्ग

जब हम भगवान श्रीकृष्ण के जीवन को देखते हैं, तो यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं लगता, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य धारा प्रतीत होती है जो मनुष्य के भीतर भक्ति, प्रेम, ज्ञान और वैराग्य को एक साथ प्रवाहित करती है। उनका जीवन स्थिर नहीं रहा, बल्कि हर चरण में उन्होंने एक नए स्थान को अपनी लीला से पवित्र किया और हर स्थान को भक्ति का केंद्र बना दिया। यही कारण है कि मथुरा से लेकर द्वारका और प्रभास तक उनके कदमों के निशान आज भी जीवित हैं और हर भक्त के हृदय में श्रद्धा का प्रकाश जगाते हैं।

उनकी इस दिव्य यात्रा की शुरुआत मथुरा से होती है, जहाँ उनका जन्म एक कारागार में हुआ। यह घटना केवल एक जन्म नहीं थी, बल्कि यह उस सत्य का प्रकट होना था कि जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। मथुरा की भूमि आज भी उस चमत्कारिक क्षण की साक्षी है, जहाँ अंधकार के बीच दिव्यता ने जन्म लिया और संसार को आशा का नया संदेश दिया। यहाँ आकर भक्त केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि अपने भीतर उस प्रकाश को अनुभव करता है जो जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकता है।

जन्म के तुरंत बाद जब संकटों का भय बढ़ा, तब श्रीकृष्ण को गोकुल ले जाया गया। गोकुल की वह पावन भूमि, जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के स्नेह में उनका पालन-पोषण हुआ, आज भी बाल-कृष्ण की निश्छल लीलाओं से गूंजती है। यहाँ की गलियों में माखन चुराने की कथाएँ और यशोदा की ममता भरी छवि हर भक्त के मन को आनंद से भर देती है। गोकुल हमें यह सिखाता है कि भक्ति का पहला स्वरूप प्रेम और सरलता है, जहाँ कोई आडंबर नहीं, केवल हृदय की सच्चाई होती है।

इसके बाद वृंदावन में श्रीकृष्ण का जीवन प्रेम की पराकाष्ठा बन जाता है। यहाँ राधा और कृष्ण का संबंध केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। वृंदावन की रासलीलाएँ यह बताती हैं कि जब भक्ति अपने चरम पर पहुँचती है, तो वह प्रेम में परिवर्तित हो जाती है और उस प्रेम में भक्त स्वयं को भूलकर ईश्वर में लीन हो जाता है। वृंदावन का हर कण, हर वृक्ष और हर गली उस दिव्य अनुभूति से भरी हुई है, जो मनुष्य को अपने भीतर झांकने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करती है।

किशोर अवस्था में नंदगांव और बरसाना की लीलाएँ हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में आनंद और प्रेम का कितना महत्व है। नंदगांव की सरलता और बरसाना का प्रेम मिलकर एक ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं, जहाँ भक्त अपने सारे दुख और चिंताओं को भूलकर केवल ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। बरसाना, जो राधा जी की नगरी है, हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, वहाँ केवल समर्पण और प्रेम ही सर्वोपरि होता है।

जब समय आया ज्ञान प्राप्त करने का, तब श्रीकृष्ण उज्जैन पहुँचे, जहाँ गुरु संदीपनि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल भावनाओं का विषय नहीं है, बल्कि उसमें ज्ञान और अनुशासन का भी उतना ही महत्व है। यहाँ श्रीकृष्ण ने यह दिखाया कि एक सच्चा साधक वही है, जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है और ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाता है।

इसके बाद जब जीवन में जिम्मेदारियाँ आईं, तब श्रीकृष्ण ने द्वारका को अपनी कर्मभूमि बनाया। द्वारका में उनका रूप एक आदर्श शासक का है, जहाँ उन्होंने समाज को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों में भी प्रकट होनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हैं, तब वही भक्ति का सर्वोच्च रूप बन जाता है।

महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान केवल युद्धभूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए मार्गदर्शन है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ कर्म और ध्यान का अद्भुत संतुलन होता है।

अंततः सोमनाथ के प्रभास क्षेत्र में श्रीकृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर लीला का एक अंत होता है और अंततः आत्मा को अपने मूल स्वरूप में लौटना होता है। यह वैराग्य का वह क्षण है, जहाँ मनुष्य सब कुछ छोड़कर केवल परम सत्य की ओर बढ़ता है।

श्रीकृष्ण के इन सभी धामों की यात्रा हमें यह समझाती है कि जीवन के हर चरण में भक्ति का एक नया रूप होता है—कहीं वह प्रेम है, कहीं ज्ञान है, कहीं कर्तव्य है और कहीं वैराग्य। जब हम इन सभी रूपों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह यात्रा केवल स्थानों की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जो हमें हमारे भीतर बसे ईश्वर तक ले जाती है।

कान्हा की यह लीला-यात्रा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए केवल सच्चे हृदय और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। जब यह भावना हमारे भीतर जागृत हो जाती है, तब हमारा जीवन भी एक पवित्र यात्रा बन जाता है, जहाँ हर क्षण में हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है और हमारा हृदय भक्ति के आनंद से भर जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से अहमदाबाद में फिक्की के 100 वर्ष के उत्सव का शुभारंभ

▸▸ मुख्यमंत्री का फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रेरक संबोधन

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहलों से भारत आत्मनिर्भरता से विकास की राह पर दौड़ने लगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ विकसित भारत-2047 में विकसित गुजरात-2047 से गुजरात अग्रसर रहेगा

▸▸ सेमीकंडक्टर, ग्रीन ग्रोथ सहित इमर्जिंग सेक्टर्स में गुजरात को हब बनाने की मंशा है

▸▸ विकसित गुजरात-2047 रोडमैप से 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी तक ले जाने का लक्ष्य रखा है

▸▸ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वुमन-लेड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को साकार करने हेतु राज्य में महिला स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अहमदाबाद में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) की स्थापना के 100 वर्ष के उत्सव का शुभारंभ कराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में फिक्की के 100 वर्ष का उत्सव तथा देश का अमृतकाल फिक्की के लिए डबल बोनांजा है।

श्री पटेल ने फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रेरक संबोधन देते हुए देश के सबसे पुराने, प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली उद्योग मंच के रूप में फिक्की की 100 वर्ष की सफल यात्रा को मील का पत्थर बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहलों से भारत आत्मनिर्भरता से विकास की राह पर दौड़ने लगा है। इसमें भी फिक्की का उल्लेखनीय सहयोग मिला है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में गुजरात की विकास यात्रा की प्रभावी प्रस्तुति देते हुए कहा कि गुजरात ने देश और दुनिया को बताया है कि दृष्टिवान नेतृत्व तथा डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट से कितनी स्पीड और कितने स्केल के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात देश की जीडीपी में 8.3 प्रतिशत, नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 18 प्रतिशत और देश के कुल निर्यात में 27 प्रतिशत योगदान के साथ अग्रसर है।

उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए विकसित गुजरात-2047 का रोडमैप तैयार करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। इस रोडमैप अंतर्गत 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर, एआई तथा ग्रीन ग्रोथ जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स पर फोकस किया है। हाल ही में साणंद में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कराए गए दो सेमीकंडक्टर प्लांट्स द्वारा गुजरात अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। इतना ही नहीं; गिफ्ट सिटी में कार्यरत एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा सेंटर तथा फिनटेक राज्य को विभिन्न इमर्जिंग सेक्टर्स में अधिक मजबूत बनाएंगे। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आईटी तथा आईटीईएस पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी जैसी प्रोत्साहक नीतियों से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट तथा विश्व के उद्योगों के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बना है। आज विश्व की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 100 गुजरात में कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वुमन डेवलपमेंट नहीं, बल्कि वुमन-लेड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके अनुरूप गुजरात में महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में 'हर स्टार्टअप' प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है।

उन्होंने गुजरात को व्यापार-उद्योग के वर्ल्ड मैप पर प्रतिष्ठा दिलाने वाली वाइब्रेंट गुजरात समिट की सफलता में प्रारंभ से ही फिक्की के नेशनल पार्टनर के रूप में सहयोगी रहने की भी सराहना की।

उन्होंने प्रधानमंत्री के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को साकार करके विकसित भारत-2047 के निर्माण के लिए फिक्की के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

फिक्की के अध्यक्ष श्री अनंत गोयनका ने शताब्दी के लॉन्चपैड के रूप में अहमदाबाद के रणनीतिक चयन का उल्लेख करते हुए राज्य की उद्योगोन्मुखी नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रो-एक्टिव पॉलिसीज तथा निजी उपक्रमों के बीच समन्वय देश के अन्य राज्यों के लिए भी ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है।

उन्होंने कहा कि गुजरात ने सिद्ध किया है कि किस प्रकार राज्य सरकार की नीतियाँ आर्थिक लैंडस्केप को बदल सकती हैं। जिस प्रकार समग्र देश विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार फिक्की भी गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं तथा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है।

इस अवसर पर फिक्की की गुजरात राज्य परिषद् के अध्यक्ष श्री गोकुल जयकृष्णन ने स्टार्टअप्स तथा ग्रीन एनर्जी के लिए हब के रूप में राज्य की भूमिका पर बल दिया।

समारोह में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विजय शंकर, उपाध्यक्ष श्री पुनीत दालमिया, महासचिव श्री अनंत स्वरूप, महानिदेशक श्री ज्योति विज सहित फिक्की के पदाधिकारी, अग्रणी और उद्यमी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा पालनपुर–अहमदाबाद खंड पर गति क्षमता बढ़ाने हेतु कार्य प्रगति पर

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा पालनपुर–अहमदाबाद रेलखंड पर ट्रेनों की गति क्षमता को 130 किमी/घंटा तक बढ़ाने के उद्देश्य से अवसंरचना सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में करजोड़ा–पालनपुर स्टेशनों के मध्य स्थित प्रमुख पुल संख्या 867 के अप्रोच पर जियो सेल एवं ब्लैंकेटिंग सामग्री डाली जा रही है। इस कार्य के पूर्ण होने पर इस खंड पर ट्रेनों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों का यात्रा समय कम होगा और वे अपने गंतव्य तक अधिक शीघ्रता से पहुँच सकेंगे। साथ ही, मालगाड़ियों की तेज एवं सुचारु आवाजाही से माल परिवहन प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी, जिससे समग्र रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। उक्त कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए दिनांक 21 अप्रैल 2026 (मंगलवार) को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 14822 (साबरमती–जोधपुर) दिनांक 22 अप्रैल 2026 को साबरमती–आबूरोड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा 24 अप्रैल को साबरमती–दुर्गापुर समर स्पेशल ट्रेन का संचालन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती–दुर्गापुर–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09413/09414 साबरमती–दुर्गापुर–साबरमती स्पेशल (विशेष किराया पर)

ट्रेन संख्या 09413 (साबरमती–दुर्गापुर स्पेशल) दिनांक 24 अप्रैल, 2026 को साबरमती से 18:25 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 09:15 बजे दुर्गापुर पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09414 (दुर्गापुर–साबरमती स्पेशल) दिनांक 26 अप्रैल, 2026 को 12:15 बजे दुर्गापुर से प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 03:00 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, इंदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल एवं अण्डाल स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन सं. 09413 (साबरमती–दुर्गापुर स्पेशल) के लिए आरक्षण की बुकिंग 22 अप्रैल, 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

इस ट्रेन में 3-टियर एसी एवं स्लिपर श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

जनता की शिकायतों और समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का 'स्वागत' कार्यक्रम आगामी गुरुवार, 23 अप्रैल को आयोजित नहीं होगा

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2026 का राज्य और जिला स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम गुरुवार, 30 अप्रैल, 2026 को आयोजित होगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम आगामी गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को आयोजित नहीं होगा। राज्य में स्थानीय निकाय के चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को आयोजित होने वाला राज्य और जिला स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होने वाले इस 'स्वागत' कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल 2026 का राज्य और जिला स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम पांचवें गुरुवार यानी 30 अप्रैल, 2026 को आयोजित होगा।

इतना ही नहीं, उस दिन सुबह 8 से 11 बजे तक लोगों के अभ्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई के विशेष कार्य अधिकारी ने सभी संबंधित लोगों से 'स्वागत' कार्यक्रम के आयोजन में हुए इस बदलाव को ध्यान में लेने का अनुरोध किया है।

गर्मी में शीतलता, सौंदर्य और सेहत का खजाना: गोंद कतीरा का कमाल -शहनाज़ हुसैन

(जीएनएस)। गोंद कतीरा एक प्राकृतिक गोंद है जिसे गर्मियों के स्वास्थ्य बर्धक पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है । यह एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जो एस्ट्रैगलस पौधे की प्रजाति के रस को सुखाकर बनाया जाता है।। यह गम ड्रैगन या ट्रैगाकैंथ गोंद भी कहलाता है। सूखने पर यह छोटे, हल्के और थोड़े सख्त टुकड़ों के रूप में दिखाई देता है। इसका रंग आमतौर पर सफेद से हल्के भूरे रंग का होता है। यह बाहर से कठोर और सूखा दिखता है, लेकिन पानी में डालने से यह मुलायम, हल्के और पारदर्शी जेल की तरह फूलने लगता है। इसका हाइड्रेटिंग जेल रूप नमी बनाए रखने और त्वचा की लोच को अंदर से बाहर तक बढ़ाने में मदद करता है।

यह हलकी गंध और स्वाद का होता है । नियमित रूप में पेय के रूप में इसका सेवन करने से यह शरीर को ठंडक देता है, और पाचन शक्ति और एनर्जी भी बढ़ाता है. यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम से भरपूर होता है। इसमें अल्कलॉइड और लगभग 3% प्रोटीन होते हैं।

त्वचा और बालों के लिए उपयोगी: गोंद कतीरा शरीर में नमी बढ़ाता है, । फोड़े-फुंसियां होने के पीछे सबसे बड़ा कारण शरीर की गर्मी होती है । इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है और यह शरीर की गर्मी को कम करता है जिससे जिससे गर्मी के कारण होने वाले मुंहासे, फुंसियां और ब्रेकआउट्स कम होते हैं। । इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की जलन को भी शांत करते हैं और कील मुहांसों को दूर करने में बहुत प्रभावी होते हैं । यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर पेट को ठंडा रखता है।कील मुहांसो से लड़ने के लिए गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स ड्रिंक काफी फायदेमंद माना जाता है ।इसके लिए 1 चम्मच गोंद कतीरा को रात भर थोड़े पानी में भिगो दें ताकि यह फूल जाए। 1 चम्मच सब्जा के बीज आधा घण्टा के लिए थोड़े पानी में भिगो दें।

1 गिलास नारियल पानी और थोड़ा सा नींबू का रस या शहद ले लें । एक कांच के कटोरे में गोंद कतीरा के जैल में भीगे हुए सब्जा के बीज डाल दीजिये । अब इसमें नारियल पानी मिलाएं और अंत में नींबू का रस या शहद मिला दें। इस ड्रिंक को आप सुबह दिन के किसी भी समय ले सकते हैं लेकिन खाली पेट लेने से अच्छे परिणाम मिलेंगे । नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपको कुछ ही हफ्तों में अपनी स्किन में फर्क महसूस होने लगेगा।

गोंद कतीरा को रातभर भिगो लें ।सुबह इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालें और इसके बाद आधा नींबू का रस मिला लें। इसे आप पी लें।इसके लगातार सेवन से कुछ ही दिनों में असर दिखना शुरू हो जायेगा । ये शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करके मुहांसे, झुर्रियों और सनबर्न जैसी समस्याओं को कम करता है जिससे त्वचा कोमल और आकर्षक दिखती है । भीगे हुए गोंद कतीरा के जेल को फेस पैक की तरह सीधे चेहरे लगा लें और आधा घण्टा बाद साफ़ पानी से धो डालें । मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा की जलन में आराम मिलता है।

गोंद कतीरा में एंटी-एजिंग गुण होते हैं। यह घाव भरने और दाग-धब्बों को कम करने के साथ-साथ पिम्पल्स को भी दूर करता है। इसके अलावा, इसके पोषक तत्व बालों को जड़ों से मज़बूत बना सकते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रेटिंग गुण स्कैल्प को ठंडक पहुंचाते हैं, बालों का टूटना कम करते हैं और रूखेपन से राहत दिलाते हैं। गोंद कतीरा में मौजूद पोषक तत्व बालों को जड़ों से मजबूत, घना और चमकदार बना सकते हैं। रात भर भीगे गोंद कतीरे को सुबह शर्बत या दूध के साथ लेने से भी बालों को अंदरूनी पोषण मिलता है।

'ऑपरेशन देव' का खुलासा: चार राज्यों में फैले बाल तस्करी गिरोह पर बड़ी चोट, मासूमों की खरीद-फरोख्त का काला सच सामने

(जीएनएस)। अहमदाबाद/नई दिल्ली। देश को झकझोर देने वाले एक संगठित बाल तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गुजरात पुलिस ने 'ऑपरेशन देव' के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। यह ऑपरेशन केवल एक अपहरण मामले की जांच से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे परतें खुलती गईं, एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ, जो नवजात और नाबालिग बच्चों की खरीद-फरोख्त को अपना कारोबार बना चुका था। चार राज्यों में फैले इस नेटवर्क ने समाज के सामने एक गंभीर और भयावह सच्चाई रख दी है।इस पूरे मामले की शुरुआत चार वर्षीय बच्चे 'देव' के अपहरण से हुई थी। शुरुआत में यह एक सामान्य किडनैपिंग केस लग रहा था, लेकिन जांच के दौरान एक जुवेनाइल से मिली अहम जानकारी ने पुलिस को ऐसे सुराग दिए, जिन्होंने इस केस को राष्ट्रीय स्तर के बाल तस्करी नेटवर्क तक पहुंचा दिया। इसी के बाद इस मिशन को 'ऑपरेशन देव' नाम दिया गया और जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया गया।

तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल ट्रैकिंग और आधुनिक एआई टूल्स की मदद से पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना मुरुगन तक पहुंच बनाई, जिसे कागजनगर से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही करीमनगर क्षेत्र से तिरुपति, मल्लैया और गंगाधर नामक आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ ही यह साफ हो गया कि यह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध अपराध नेटवर्क है।

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह नवजात बच्चों को जन्म के महज 24 से 48 घंटे के भीतर ही बेच देता था। इस अमानवीय धंधे में अस्पतालों, दलालों और परिवहन के माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाता था, ताकि किसी को शक न हो। अब तक कम से कम आठ बच्चों की बिक्री की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि पुलिस को आशंका है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

इस नेटवर्क की जड़ें केवल एक राज्य तक सीमित नहीं थीं। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इन समन्वित कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था और राज्यों के बीच तालमेल बनाकर अपने नेटवर्क को मजबूत कर चुका था।

पुलिस के अनुसार, मुरुगन पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस बार की जांच में उसकी पत्नी कृष्णावेणी की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसे भी आरोपी बनाया गया है। यह तथ्य इस गिरोह की पारिवारिक और संगठित संरचना को दर्शाता है, जहां अपराध केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क के रूप में संचालित हो रहा था।

इस ऑपरेशन का एक अहम मोड़ तब आया जब पुलिस ने एक आरोपी को बस में एक बच्चे के साथ पकड़ा। यही गिरफ्तारी इस पूरे रैकेट की कड़ियों को जोड़ने में निर्णायक साबित हुई। इसके बाद एक-एक कर कई सुराग सामने आते गए और अंततः पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि बाल तस्करी जैसे अपराध केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह समाज के नैतिक ताने-बाने पर भी गहरा आघात हैं। ऐसे मामलों में अक्सर गरीब परिवारों की मजबूरी, जागरूकता की कमी और अपराधियों की चालाकी का फायदा उठाया जाता है।

फिलहाल, पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 'ऑपरेशन देव' ने न केवल एक बड़े अपराध का पर्दाफाश किया है, बल्कि यह भी उम्मीद जगाई है कि समय रहते कई मासूम बच्चों को इस भयावह जाल से बचाया जा सकेगा।

इस कार्रवाई ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के लंबे हाथ अब ऐसे संगठित अपराधों तक पहुंच रहे हैं, और बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सोना वायदा में 243 रुपये, चांदी वायदा में 1576 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 5 रुपये की नरमी

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 18599.32 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 318813.5 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 12155.60 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37119 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 337413.93 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 18599.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 318813.5 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 37119 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2446.6 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 12155.60 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 153800 रुपये के भाव पर खूलकर, 153992 रुपये के दिन के उच्च और 153360 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153943 रुपये के पिछले बंद के सामने 243 रुपये या 0.16 फीसदी लुढ़ककर 153700 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 88 रुपये या 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 122744 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 11 रुपये या 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 15383 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 152064 रुपये के भाव पर खूलकर, 152600 रुपये के दिन के उच्च और 151920 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 33 रुपये या 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 152373 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 152505 रुपये के भाव पर खूलकर, 152847 रुपये के दिन के उच्च और 152110 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 152571 रुपये के पिछले बंद के सामने 72 रुपये या 0.05 फीसदी की बढ़त के साथ 152643 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 250428 रुपये के भाव पर खूलकर, 251969 रुपये के दिन के उच्च और 250210 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 252545 रुपये के पिछले बंद के सामने 1576 रुपये या 0.62 फीसदी की गिरावट के साथ 250969 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 721 रुपये या 0.28 फीसदी गिरकर 253202 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 745 रुपये या 0.29 फीसदी की गिरावट के साथ 253231 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। मेटल वर्ग में 2298.59 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 2.65 रुपये या 0.21 फीसदी की तेजी के संग 1272.05 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 3.45 रुपये या 1.01 फीसदी की मजबूती के साथ 343.9 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 1.5 रुपये या 0.41 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 366.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

जबकि सीसा अप्रैल वायदा 2.5 रुपये या 1.28 फीसदी की बढ़त के साथ 197.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4028.81 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 8104 रुपये के भाव पर खूलकर, 8212 रुपये के दिन के उच्च और 8022 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 5 रुपये या 0.06 फीसदी की गिरावट के साथ 8179 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 6 रुपये या 0.07 फीसदी औंधकर 8176 रुपये प्रति बैरल पर आ गया।

इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 248.9 रुपये के भाव पर खूलकर, 251.7 रुपये के दिन के उच्च और 247.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 251.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 30 पैसे या 0.12 फीसदी की नरमी के साथ 251.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 30 पैसे या 0.12 फीसदी घटकर 251.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 993.9 रुपये के भाव पर खूलकर, 4.8 रुपये या 0.48 फीसदी की मजबूती के साथ 1008.5 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6436.41 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5719.19 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1528.95 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 355.89 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 64.60 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 342.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 2699.61 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1319.61 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.48 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9992 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61177 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27435 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 377316 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63001 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7991 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 26371 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 91763 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14075 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 39361 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 37104 पॉइंट पर खूलकर, 37141 के उच्च और 37104 के नीचले स्तर को छूकर, 72 पॉइंट घटकर 37119 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 24.5 रुपये की बढ़त के साथ 258.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 95 पैसे की नरमी के साथ 4.7 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 81 रुपये की गिरावट के साथ 569 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 869 रुपये की गिरावट के साथ 1580 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.05 रुपये की गिरावट के साथ 2.77 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.28 रुपये की गिरावट के साथ 1.04 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 18.5 रुपये की बढ़त के साथ 185.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 45 पैसे की नरमी के साथ 3.55 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 17.5 रुपये की गिरावट के साथ 351.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1 रुपये की बढ़त के साथ 384.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1050 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 10 पैसे की नरमी के साथ 0.27 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1 पैसे के सुधार के साथ 0.02 रुपये हुआ।

सोशल मीडिया से साजिश तक: गुजरात ATS की कार्रवाई में उजागर हुआ खतरनाक नेटवर्क

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बार फिर यह चेतावनी सामने आई है कि आधुनिक दौर में खतरनाक विचारधाराएं किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं तक पहुंच रही हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड की हालिया कार्रवाई ने इस सच्चाई को और गहराई से उजागर कर दिया है, जिसमें दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो देश के खिलाफ गंभीर साजिश रचने के आरोप में जांच के घेरे में आए हैं। गुजरात ATS द्वारा की गई इस कार्रवाई में जिन दो आरोपियों को पकड़ा गया, उनमें इरफान खान पठान और मुर्शिद जाहिद अख्तर शेख शामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये दोनों युवक बीते कई महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय थे और एक सीमित लेकिन बेहद संवेदनशील समूह का हिस्सा बन चुके थे। यह समूह कथित तौर पर भारत के खिलाफ उग्र विचारधाराओं से प्रभावित होकर चर्चाएं कर रहा था और देश में अस्थिरता फैलाने की सोच को बढ़ावा दे रहा था।

जांच अधिकारियों के मुताबिक, इन युवकों का झुकाव अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन ISIS जैसी चरमपंथी विचारधाराओं की ओर था। हालांकि अभी तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इन्हें किसी बाहरी हैंडलर द्वारा सीधे निर्देश नहीं दिए जा रहे थे, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया सोशल मीडिया के जरिए हुई, जिसे सुरक्षा एजेंसियां 'सेल्फ-रेडिकलाइजेशन' के रूप में देख रही हैं। यह स्थिति इसलिए और गंभीर मानी जा रही है क्योंकि इसमें बाहरी नेटवर्क की भूमिका सीमित दिखाई देती है, लेकिन विचारधारा का प्रभाव बेहद गहरा होता है।

बताया जा रहा है कि पिछले सात महीनों के दौरान ये युवक WhatsApp

और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार सक्रिय रहे और एक छोटे लेकिन बंद समूह के जरिए विचारों का आदान-प्रदान करते रहे। इस समूह में करीब 12 से 13 सदस्य शामिल थे, जो एक-दूसरे से जुड़े हुए थे और देश के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यह नेटवर्क भले ही शुरुआती स्तर पर था, लेकिन इसकी दिशा और सोच बेहद चिंताजनक थी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पृष्ठभूमि भी इस मामले को और गंभीर बनाती है। इरफान खान पठान, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर का निवासी है। उसने मेहसाणा से MSc केमिस्ट्री की पढ़ाई की है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरा आरोपी मुर्शिद जाहिद अख्तर शेख, 21 वर्ष का है और मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और मुंबई में अपने भाई के साथ बिरयानी की दुकान में काम करता था।

दोनों आरोपियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को विशेष रूप से संवेदनशील मान रही हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि किस तरह सामान्य पृष्ठभूमि के युवा भी गलत विचारधाराओं के प्रभाव में आकर देश विरोधी गतिविधियों की ओर बढ़ सकते हैं। गुजरात ATS को इस पूरे मामले में एक अहम सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। इरफान को सिद्धपुर से और मुर्शिद को मुंबई से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क के अन्य सदस्य कौन हैं और क्या इसके तार किसी बड़े संगठन या साजिश से जुड़े हुए हैं।

जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों युवक हथियारों और फंडिंग से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी ठोस हमले की योजना बनाई थी या नहीं, लेकिन जिस तरह के विषयों पर बातचीत हो रही थी, उससे एजेंसियों को यह आशंका है कि भविष्य में यह नेटवर्क एक गंभीर खतरा बन सकता था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और जागरूकता कितनी जरूरी है। डिजिटल युग में जहां एक ओर जानकारी तक पहुंच आसान हो गई है, वहीं दूसरी ओर गलत और खतरनाक विचारधाराएं भी तेजी से फैल रही हैं। ऐसे में युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और उन्हें इन प्रभावों से बचाना समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 'सेल्फ-रेडिकलाइजेशन' की प्रवृत्ति आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, क्योंकि इसमें व्यक्ति बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के ही कट्टर विचारों से प्रभावित हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है और जब तक इसका पता चलता है, तब तक व्यक्ति काफी हद तक उस सोच में डूब चुका होता है।

गुजरात ATS की इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। समय रहते की गई इस कार्रवाई ने संभावित खतरे को टाल दिया है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए और अधिक सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता होगी।

फिलहाल, दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क के तार देश के बाहर तक जुड़े हुए हैं या यह केवल स्थानीय स्तर तक सीमित था।

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि विचारों के स्तर पर भी चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में समाज, परिवार और प्रशासन को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि युवा सही दिशा में आगे बढ़ें और किसी भी तरह की भ्रामक या खतरनाक विचारधारा का शिकार न बनें।

कमजोर मानसून की आशंका के बीच सरकार का बड़ा दांव, 10 लाख टन चना खरीदकर बनाएगी बफर स्टॉक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संभावित कमजोर मानसून और वैश्विक मौसमीय प्रभावों के बीच केंद्र सरकार ने देश में दालों की उपलब्धता और कीमतों को संतुलित रखने के लिए बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। सरकार लगभग 10 लाख टन चना खरीदकर बफर स्टॉक तैयार करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में आपूर्ति संकट और महंगाई की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मौसम विशेषज्ञों ने इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, इस बार मानसून सामान्य से करीब 8 प्रतिशत तक कम रह सकता है। इसके साथ ही अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना भी जताई गई है, जो आमतौर पर वर्षा में कमी और सूखे जैसे हालात पैदा करता है। ऐसे परिदृश्य में दलहन फसलों, विशेषकर चना, की पैदावार पर असर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।

सरकार की इस खरीद नीति का उद्देश्य दोहरा है। एक तरफ यह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उचित दाम सुनिश्चित करेगा, वहीं दूसरी ओर बाजार में दालों की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा। सरकारी एजेंसियां सीधे किसानों से खरीद करेंगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा।

चना भारत में सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसलों में से एक है, जिसका उपयोग रोजमर्रा के भोजन में व्यापक रूप से होता है। ऐसे में इसकी कीमतों में अचानक वृद्धि आम उपभोक्ताओं के बजट पर सीधा असर डालती है। सरकार पहले भी मूल्य स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक का सहारा लेती रही है, लेकिन इस बार संभावित मौसमीय जोखिम को देखते हुए पहले से तैयारी की जा रही है।

हालांकि, मौजूदा आंकड़े कुछ राहत देने वाले भी हैं। वित्त वर्ष 2026 में देश में चना उत्पादन लगभग 6.2 प्रतिशत बढ़कर 11.8 मिलियन टन तक पहुंच गया है। प्रति हेक्टेयर उपज में भी 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1,238 किलोग्राम तक पहुंची है। यह वृद्धि दर्शाती है कि किसानों ने बेहतर तकनीक और अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाया है। इसके अलावा, आयात शुल्क में वृद्धि जैसे नीतिगत फैसलों ने भी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। लेकिन मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए केवल उत्पादन वृद्धि पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। यही कारण है कि सरकार ने अतिरिक्त भंडारण की रणनीति अपनाई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बाजार में आपूर्ति बनाए रखी जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करेगा। अगर मानसून कमजोर रहता है और उत्पादन में गिरावट आती है, तो यही बफर स्टॉक कीमतों को अनियंत्रित होने से रोकने में अहम भूमिका निभाएगा।

कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला एक दूरदर्शी आर्थिक और कृषि नीति का संकेत देता है, जिसमें संभावित संकट को पहले से भांपकर उसके समाधान की तैयारी की जा रही है। आने वाले महीनों में मानसून की स्थिति और बाजार की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि यह रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है, लेकिन फिलहाल यह कदम देश की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

हत्या के बाद सख्ती: धंधुका में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, सुरक्षा के बीच प्रशासन का बड़ा अभियान

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात के धंधुका में युवक धर्मेश गामरा की हत्या के बाद उपजे तनाव के बीच अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ओवरटेक को लेकर हुए विवाद ने जिस तरह हिंसक रूप ले लिया था और दो समुदाय आमने-सामने आ गए थे, उसके बाद इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। घटना के दो दिन बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध कब्जों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है, जिसे इलाके में शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मंगलवार को प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ धंधुका के खटकीवाड़ इलाके में पहुंची, जहां अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। शुरुआती चरण में चार अवैध कब्जों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाया गया। इसके साथ ही धंधुका-बगोदरा हाईवे पर भी अवैध अतिक्रमण हटाने की तैयारी की गई है, ताकि सड़क मार्ग पूरी तरह साफ हो सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके।

यह कार्रवाई केवल सामान्य अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हाल ही में हुए धर्मेश गामरा हत्याकांड से भी जोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने उन स्थानों को भी चिन्हित किया है, जो आरोपियों के घरों के आसपास स्थित हैं और जहां सड़क पर अवैध कब्जे पाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन अतिक्रमणों को हटाना जरूरी है, ताकि क्षेत्र में कानून का राज स्थापित किया जा सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके।

धंधुका के उपखंड अधिकारी विद्यासागर ने स्पष्ट किया कि इस पूरी कार्रवाई के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर अवैध निर्माण पाए गए, उन्हें पहले नोटिस दिए गए थे और उसके बाद ही यह अभियान चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध कब्जों को हटाया जाता है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

धंधुका-बगोदरा हाईवे पर फ्लाईओवर से लेकर धंधुका चौक तक के क्षेत्र को भी प्रशासन ने चिन्हित किया है, जहां अतिक्रमण हटाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस दौरान आरोपी के घर को भी हटाने की बात कही गई है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति या निर्माण नहीं टिक सकता।

इस पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कोई ढिलाई नहीं बरती है। आस्था राणा, जो अहमदाबाद ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक हैं, ने बताया कि अभियान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लगभग 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके लिए दो अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं।

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया है। पूरे इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। इसके अलावा मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमों को भी तैनात किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक ओर कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सख्त कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी तरह के अवैध कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

धर्मेश गामरा हत्याकांड के बाद जिस तरह से इलाके में तनाव फैला था, उसने प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है, अगर समय रहते स्थिति को नियंत्रित न किया जाए। ऐसे में प्रशासन का यह अभियान न केवल अवैध कब्जों को हटाने का प्रयास है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि कानून के खिलाफ कोई भी गतिविधि सहन नहीं की जाएगी।

फिलहाल धंधुका में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क बना हुआ है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और लगातार निगरानी के चलते किसी भी तरह की नई घटना को रोकने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सख्ती इलाके में स्थायी शांति स्थापित करने में कितनी सफल होती है।

दावत बनी आफत: दाहोद में शादी का भोज पड़ा भारी, 400 से अधिक लोग बीमार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। खुशियों और उत्सव का माहौल कब अचानक चिंता और अफरा-तफरी में बदल जाए, इसका ताजा उदाहरण गुजरात के दाहोद जिले के अबोलोड गांव में देखने को मिला, जहां एक शादी समारोह में शामिल सैकड़ों लोगों के लिए दावत जहरीली साबित हो गई। करीब 1200 मेहमानों की मौजूदगी में आयोजित इस शादी में भोजन करने के कुछ ही घंटों बाद 400 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम के समय गांव के लोग और दूर-दराज से आए मेहमानों ने खुशी-खुशी दावत का आनंद लिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भोजन के लगभग दो घंटे बाद ही कई लोगों को पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ती चली गई और उल्टी-दस्त जैसे लक्षण सामने आने लगे। शुरुआत में कुछ बुजुर्ग प्रभावित हुए, लेकिन जल्द ही बच्चे, युवा और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ गए।

सायरन लगातार गूंज रहे थे, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी अधिक थी कि सभी को तुरंत एम्बुलेंस मिल पाना संभव नहीं था। ऐसे में परिजन अपने-अपने निजी वाहनों, बाइक, ऑटो या जो भी साधन उपलब्ध थे, उनसे बीमारों को अस्पताल पहुंचाने लगे। जैसे ही मरीजों को जाइडस अस्पताल लाया जाने लगा, वहां भी स्थिति तेजी से गंभीर होती चली गई। एक साथ सैकड़ों मरीजों के पहुंचने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रात होते-होते मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच गई, जिससे अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को युद्धस्तर पर काम करना पड़ा। हर तरफ मरीजों की भीड़, परिजनों की चिंता और इलाज के लिए भागदौड़ का दृश्य देखने को मिला।

डॉक्टरों ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया और सभी मरीजों को अलग-अलग वार्ड में भर्ती कर उनकी स्थिति पर नजर रखी। कई मरीजों को ड्रिप और जरूरी दवाएं दी गईं, ताकि उनकी हालत को स्थिर किया जा सके। अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ को भी बुलाया, जिससे इलाज में किसी तरह की कमी न रह जाए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी तुरंत सक्रिय हो गए। महेंद्रभाई भाभोर, जो गरबाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं, रात में ही अस्पताल पहुंचे और मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों से बात कर इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी मरीज को उपचार में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि शादी में परोसे गए भोजन में किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण यह सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है। खासतौर पर पनीर की सब्जी और आम के रस को संदेह के दायरे में रखा गया है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर भोजन के नमूने एकत्रित कर लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर इस घटना के पीछे असली कारण क्या था।

इस घटना ने एक बार फिर बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व को उजागर कर दिया है। अक्सर शादी या बड़े समारोहों में भोजन की गुणवत्ता और उसके रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका परिणाम इस तरह की गंभीर घटनाओं के रूप में सामने आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है।

गांव के लोगों के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं है। जहां एक ओर शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं कुछ ही घंटों में पूरा माहौल चिंता और भय में बदल गया। कई परिवार अपने बीमार सदस्यों को लेकर परेशान नजर आए, जबकि कुछ लोग अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपने परिजनों की खबर का इंतजार करते रहे।

फिलहाल अधिकांश मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है और सभी प्रभावित लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

दाहोद की यह घटना एक चेतावनी भी है कि किसी भी बड़े आयोजन में भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षा मानकों का पालन करना कितना जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

राजस्थान में "सार्थक नाम अभियान": विद्यार्थियों के अपमानजनक नाम बदलने का प्रयास

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के उन नामों को सुधारने का प्रयास कर रही है जिनका अर्थ "छोटा", "काला", "शेर" और ऐसे ही अन्य नाम हैं। अब राजस्थान के स्कूलों में ऐसे नामों की अनुमति नहीं होगी। जी हां, भारत में छोटे बच्चों को दिए जाने वाले आम "प्यार के नाम" राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने "सार्थक नाम अभियान" शुरू किया है। विभाग का अनुमान है कि सरकारी और निजी स्कूलों में ऐसे 2000 से 3000 मामले हैं।

सरकार का दावा है कि यह पहल अनुचित, अस्पष्ट या नकारात्मक अर्थ वाले नामों को हटाने और उनके स्थान पर अधिक सार्थक और सम्मानजनक नामों को अपनाने के लिए शुरू की गई है। सरकार के अनुसार, काजोदामल, शेरू, कालू, टिंकू जैसे पारंपरिक नामों को कृष्ण, अथर्व, आरव और अखंड जैसे सम्मानजनक नामों से बदला जाना चाहिए। स्थानीय पहल समुदायों में सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं? मध्य प्रदेश के गांवों में स्थानीय पहल सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। अपशब्दों के विरुद्ध नियम लागू करके और राष्ट्रगान जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मान को बढ़ावा देकर, ये पहल अधिक सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण सामुदायिक वातावरण को बढ़ावा देती हैं। ऐसे बदलाव न केवल सार्वजनिक व्यवहार में सुधार लाते हैं, बल्कि हाशिए पर पड़े समूहों को भी सशक्त बनाते हैं। इससे समुदाय का समग्र कल्याण होता है। मंत्री ने कहा कि सरकारी अभिलेखों से जाति आधारित या अपमानजनक शब्दों को हटाना अत्यंत आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट : मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध हिंदू धर्म के लिए हानिकारक हो सकता है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले सप्ताह टिप्पणी की कि यदि मंदिर और मठ संप्रदाय के आधार पर प्रवेश प्रतिबंधित करते हैं और एक ही धर्म में संप्रदायों को अलग करते हैं, तो इसका हिंदू धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और समाज में विभाजन पैदा होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एम. वैदनाथन की इस दलील पर मौखिक टिप्पणी की कि संविधान का अनुच्छेद 26(ख) किसी धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है और यह अनुच्छेद 25(2)(ख) पर प्राथमिकता रखता है, जो राज्य को सभी सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने का अधिकार देता है।

केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में भगवान अय्यप्पा के भक्तों की ओर से वैद्यनाथन अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ने, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन और जॉयमाल्य बागची की पीठ सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति नागरत्ने ने कहा कि राज्य अनुच्छेद 25(2)(ख) के तहत हस्तक्षेप कर सकता है ताकि समाज के सभी वर्गों को मंदिरों में प्रवेश मिल सके। न्यायमूर्ति कुमार ने

वैदनाथन से यह भी कहा कि इसीलिए हमने कहा था कि इस तर्क को बहुत ऊँचा न उठाएँ। उन्होंने वैदनाथन के इस तर्क का जिक्र किया कि अनुच्छेद 26(ख) अनुच्छेद 25(2)(ख) को निरस्त करता है। यदि इस तरह अन्य लोगों को बाहर रखा जाता है, तो यह हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। इसका धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह संप्रदाय के लिए प्रतिकूल होगा। यह धर्म के लिए अनुकूल होना चाहिए।

पश्चिम रेलवे दादर एवं हजरत निजामुद्दीन,के बीच चलाएगी एसी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उनकी बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए दादर एवं हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष किराये पर एसी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 04001/04002 दादर–हजरत निजामुद्दीन एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [26 फेरे]:

ट्रेन संख्या 04001 दादर – हजरत निजामुद्दीन स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को दादर से 00:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 21:35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। यह ट्रेन 23 अप्रैल से 16 जुलाई, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04002 हजरत निजामुद्दीन – दादर स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से 23:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 22:40 बजे दादर पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अप्रैल से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, मथुरा एवं कोसी कलां स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर श्रेणी के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04001 की बुकिंग 22.04.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे भूमि से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई एवं चोरी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई

(जीएनएस)। रेल सुरक्षा बल की अंकलेश्वर टीम द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए रेलवे भूमि पर लगे पेड़ों की अवैध कटाई एवं चोरी में संलिप्त 09 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 18.04.2026 को वडोदरा मंडल के कोसाड और गोठनगाँव रेलवे स्टेशनों के मध्य रेलवे भूमि से पेड़ों को काटकर चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात रेल सुरक्षा बल,अंकलेश्वर की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की गई, जिसमें 09 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से रेलवे के बबूल के पेड़ों की

लकड़ी बरामद की गई, जिसका कुल वजन 21,985 किलोग्राम तथा अनुमानित मूल्य 1,31,910/- है। इसके अतिरिक्त चोरी में प्रयुक्त 02 ट्रक, एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन तथा 02 कुल्हाड़ियाँ भी जब्त की गईं। इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3 रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 19.04.2026 को मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच रेल सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार 09 आरोपियों में से 02 को वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है, जबकि शेष 07 आरोपियों को माननीय रेलवे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है।

वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा हेतु इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।